



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]
No. 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 134(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम क

धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम, जिसमें इस अधिसूचना के राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, उस तारीख से 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं;

ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद्) नियम, 2006 में,—

780 GI/2009

(1) नियम 3 के उप-नियम (1) में,—

(i) खंड (ख) के उप-खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(x) प्रधानमंत्री कार्यालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो..... सदस्य ।

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो..... सदस्य ।”

(xii) श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो सदस्य ।”

(ii) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ड) राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से—

(i) एक कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे कि अधिनियम की अनुसूची-1 के अधीन सूचीबद्ध या अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास वनरोपण और वृक्षरोपण तथा ग्रामीण अभियान्त्रिकी में विशेषज्ञ होगा ;

(ii) एक सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा ;

(iii) एक मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा ;

(iv) एक प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विशेषज्ञ होगा ;

(v) एक जलवायु परिवर्तन में विशेषज्ञ होगा ;

(vi) एक अभिसरण में विशेषज्ञ होगा ;

- (vii) एक विधि में विशेषज्ञ होगा ; और
(viii) एक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ होगा ;

(2) नियम (4) में उप-खंड (3) और उप-खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) नियम (3) के उप-नियम (1) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उप-खंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय परिषद् के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो राजपत्र में अपनी नियुक्ति के प्रकाशन की उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(4) नियम (3) के उप-नियम (1) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उपखंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे : परंतु यह कि इस उप-नियम और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा ।”

[फा. सं. जे-11013/1/2009-एनआरडीजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 311(अ) तारीख 25 मई, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

G.S.R. 134(E).—The following draft of certain rules further to amend the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 31 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public ;

The objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110001;

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government ;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006.

(1) In rule 3, in sub rule (1),—

(i) In clause (b), after sub-clause (ix), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—

“(x) one representative of the Prime Minister's Office not below the rank of Joint Secretary.....Member.

(xi) one representative of the Ministry of Law and Justice not below the rank of Joint Secretary.....Member.

(xii) one representative of the Ministry of Labour and Employment not below the rank of Joint Secretary.....Member.”

(ii) For clause (e), the following clause shall be substituted namely :—

“(e) eight members representing the States to be nominated by the Central Government of whom—

(i) one shall be an expert in areas of works such as water conservation, land development, afforestation and plantation and rural engineering and any other work, listed or notified under Schedule I of the Act :

(ii) one shall be an expert in social audit ;

(iii) one shall be an expert in wage employment ;

(iv) one shall be an expert in print or electronic media ;

(v) one shall be an expert in climate change ;

(vi) one shall be an expert in convergence ;

(vii) one shall be an expert in law; and

(viii) one shall be an expert in communication and information technology”.

(2) In rule (4), for sub-clauses (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(3) Every non-official member of Central Council nominated under sub-clause (i) of clause (d) and clause (e) of sub-rule (1) of rule 3 shall hold his office for a term of 1 year at a time from the date of publication of his appointment in the Official Gazette.

(4) The non-official members nominated under sub-clause (i) of clause (d) and clause (e) of sub-rule (1) of rule (3) shall be eligible for re-nomination :

Provided that no person referred to in this sub-rule and in sub-rule (3) shall hold office for more than 3 years in any case”.

[F.No.J-11013/1/2009-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, vide Notification number GSR 311(E), dated the 25th May, 2006